परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग					
विभागाध्यक्ष- संचालनालय,उद्योग					
1	लघु उद्योगों की इनामी योजना ।	राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना । राज्य के समग्र विकास में लघु उद्योगों के योगदान को सम्मानित करने के लिये चयनित उद्योगों को पुरस्कृत करना ।	200	✓ लघु उद्योगों की स्थापना में वृद्धि । ✓ चयनित 3 लघु उद्योगों को पुरस्कृत करना ।	
2	लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान ।	लघु व मध्यम-वृहद नवीन उद्योगों की स्थापना तथा उद्योग के विस्तार हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से लिये गये सावधि ऋण एवं/या कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान देकर उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना ।	40000	500 प्रकरणों में अनुदान का लाभ देना ।	
3	ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण ।	युवा बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार हेतु उद्योग स्थापित करने के लिये प्रशिक्षण ।	800	लगभग 400 युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ।	
4	पंजीकृत लघु उद्योग (सीडो इकाईयों) की तृतीय संगणना।	लघु उद्योग (सीडी इकाईयों) की तृतीय संगणना के दौरान बंद पाये गये लघु उद्योगों का अपंजीकरण ।	275	8889 लघु उद्योगों का अपंजीकरण	
5	प्रधानमंत्री रोजगार योजना ।	शिक्षित बेरोजगारों को योजनांतर्गत उनके स्वयं के रोजगार हेतु उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करवाना ।	9250	8400 शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	
6	औद्योगिक पार्को के लिये अनुदान ।	राज्य के समन्वित औद्योगिक विकास हेतु हर्बल पार्क, फूड पार्क, मेटल पार्क, अपेरल पार्क, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क आदि की स्थापना ।	1000	3 नये औद्योगिक पार्को(धमतरी, राजनांदगांव एवं रायपुर) की स्थापना ।	

परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग					
विभागाध्यक्ष- संचालनालय,उद्योग					
7	औद्योगिक तथा परियोजना सर्वेक्षण की योजना ।	नवीन उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान ।	100	03 लघु उद्योगों को अनुदान ।	
8	आई.एस.ओ. 9000 के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति ।	उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र जैसे आई.एस.ओ.-9000/14000 एवं समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान देना ।	1000	13 लघु/मध्यम उद्योगों को अनुदान (अधिकतम रु. 75000 प्रति उद्योग)	
9	अधोसंरचनात्मक सहायता अनुदान ।	नवीन उद्योगों की स्थापना/उद्योगों में विस्तार हेतु अधोसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान ।	30000	25 लधु/मध्यम उद्योगों को अधोसंरचनात्मक अनुदान (अधिकतम 25 प्रतिशत प्रति उद्योग)	
10	परियोजना प्रतिवेदन निर्माण अनुदान ।	राज्य के सभी 16 जिलों का औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण कराना ।	2000	नये उद्योग स्थापित करने में सहायता होगी ।	
11	समूह आधारित उद्योगों का विकास ।	समूह में स्थापित उद्योगों के लिये सामान्य सुविधाओं का विकास करना ।	100	उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में सुधार ।	
12	निर्यात अधोसंरचना विकास सहायता ।	राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन हेतु निर्यातक इकाईयों के लिये आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराना ।	1500	औद्योगिक क्षेत्रों से निर्यात में वृद्धि ।	
13	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान ।	नवीन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान ।	10000	50 लघु उद्योग को अनुदान ।	
14	नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना ।	राज्य के संतुलित एवं नियोजित विकास के लिये संभावना वाले जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना ।	4000	04 नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा ।	

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग					
विभागाध्यक्ष- संचालनालय,उद्योग					
15	दल्ली राजहरा-रावघाट जगदलपुर रेल लाईन ।	जगदलपुर से लौह अयस्क के भिलाई इस्पात संयंत्र तक तेजी से एवं कम लागत पर परिवहन हेतु इस रेल लाईन का निर्माण प्रस्तावित है ।	150000	रेल लाईन के निर्माण हेतु भूमिअधिग्रहण करना ।	
16	सर्वे तथा डिमार्केशन ।	नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु सर्वे एवं डिमार्केशन का कार्य ।	500	नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण ।	
17	औद्योगिक विकास हेतु सड़क, नालियां निर्माण ।	प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में सड़क एवं नालियों के निर्माण/मरम्मत तथा संधारण कर अधोसंरचना का विकास करना ।	150000	अधोसंरचना का विकास हेतु निर्माण कार्य- (पुलिया- 11 नग, सड़क - 6.55 कि.मी., नाली - 25.93 कि.मी.)	
18	औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदाय ।	प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदाय की व्यवस्था हेतु निर्माण/संधारण कर अधोसंरचना का विकास करना ।	10000	औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदाय की व्यवस्था ।	
19	औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय ।	प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था का संधारण/मरम्मत कर अधोसंरचना का विकास करना ।	1500	औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था रहने से इकाईयां लाभान्वित होंगी ।	
20	अंशपूंजी सहायता योजना ।	अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु मार्जिन मनी ऋण प्रदान करना ।	1000	आवेदन के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को अंशपूंजी सहायता ।	

परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग					
विभागाध्यक्ष- संचालनालय,उद्योग					
21	छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो. लिमि. रायपुर ।	पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण में से छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास लिमि. (वित्त प्रकोष्ठ) को विभाजन में प्राप्त देनदारियों के अंतर्गत एकमुस्त भुगतान हेतु सी.एस.आई.डी.सी.(वित्त प्रकोष्ठ) रायपुर को ऋण ।	50000	पूर्ववर्ती राज्य द्वारा निर्धारित ऋण दायित्वों का भुगातन ।	
22	औद्योगिक क्लस्टर का विस्तार सुधार	उरला एवं सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में उत्तम अधोसंरचना का विकास करने के लिये पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत् गठित मेसर्स छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड को भारत शासन की इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर अप ग्रेडेशन स्कीम (आई.आई.यू.एस) योजना के प्रावधान अनुसार ऋण उपलब्ध कराना ।	40000	उरला एवं सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता वाली अधोसंरचना विकसित ।	
23	औद्योगिक पार्को की स्थापना	जेम्स ज्वेलरी, हर्बल तथा फूडपार्क की स्थापना	166000	सड़क निर्माण- 10 कि.मी. बिजली-(250 नग विद्युत पोल 8 कि.मी. तक) पेयजल-(3 एम.एम. जी.आई.पाइप लाइन का विस्तार 8 कि.मी.)	

विभागाध्यक्ष- संचालनालय,उद्योग